बट्टे खाते डालने के हक में नहीं है, क्योंकि इसके कारण ग्रामीण ऋण प्रणाली को हानि होती है। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक ने अगस्त, 1984 में बाढ़, सूखा, चक्रवात आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को राहत तथा पुनर्वास उपलब्ध कराने के लिए स्थायी निर्देश जारी किए थे। इन निर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ यह परिकल्पना की गई है कि:—

(i) अल्पावधि के उत्पादन ऋणों का मध्यावधिक ऋणों में परिवर्तन किया जाए।

(ii) वर्तमान सावधि ऋण की किश्तों का पुनर्निर्धारण/स्थगित करना, और

(iii) आवश्यकता पर आधारित अतिरिक्त फसल/निवेश, ऋणों आदि को उपलब्ध कराना।

उत्तर प्रदेश में औद्योगिक घरानों को स्वीकृत ऋण

4556. **श्री ईश दत्त यादव:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान, वर्ष-वार, राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा उत्तर प्रदेश के बड़े औद्योगिक घरानों के लिए कितना ऋण स्वीकृत किया गया है;

(ख) क्या स्वीकृत राशि निर्धारित नियमों के अंतर्गत दी गई है; और

(ग) उत्तर प्रदेश में ऐसे औद्योगिक घरानों पर राष्ट्रीयकृत बैंकों की कितनी राशि बकाया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) से (ग) सरकारी क्षेत्र के बैंक उत्पादक उद्यमों को अपने साधारण बैंकिंग कारोबार के एक भाग के रूप में, उन की आवश्यकता पर आधारित ऋणों की जरूरतों का अनुमान लगाने के पश्चात् तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी मार्ग निर्देशों को ध्यान में रखते हुए अग्रिम स्वीकृत करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि औद्योगिक इकाइयों के आकार के अनुसार बैंकों द्वारा स्वीकृत ऋणों की धनराशि के बारे में सूचना, उनकी डाटा रिपोर्टिंग प्रणाली से प्राप्त नहीं होती है। तथापि, जून 1988, (अद्यतन उपलब्ध) की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उद्योगों को स्वीकृत ऋण सीमा और बकाया ऋण निम्नानुसार है:—

(करोड़ रुपए)

वर्ष	ऋण सीमाएं	बकाया धनराशि
जून, 1988	2588	2016
जून, 1989	3088	2511

Cut in Staff and granting of extension in various Ministries

4557. SHRI KAMKAL MORARKA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether the Ministry of Finance has issued instructions to various Ministries /Departments especially Industry Ministry to cut the staff strength to effect economy in expenditure;

(b) if so, the details thereof and whether the axe is to fall on lower staff;

(c) whether Government have reviewed the policy of granting extension/re-employment of Class-I Officers in various Ministries; and

(d) how many officers (Class-I) are on extension in various Ministries?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SHANTARAM POTDUKHE): (a) and (b) All the Ministries/Departments of the Government of India (including Ministry of Industry) have been asked to conduct a review and identify posts at different levels that could be considered for surrender/abolition.

(c) No, Sir.

(d) The information is not centrally maintained.

''म्यूचुअल फण्ड'' के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में प्राप्त राशि

4558. **श्री ईश दत्त यादव:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में ''म्यूचुअल फण्ड स्कीम'' के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कितनी राशि एकत्र की गई और इस तरह प्राप्त राशि के कितने प्रतिशत का उत्तर प्रदेश में निवेश किया गया; और